संपादकीय जागरण

सोमवार, 9 जुलाई, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 11 वि. 2075

दूसरों की पीड़ा देखकर स्वयं द्रवित हो जाना ही संत स्वभाव है

# लंबा होता इंतजार

**यह अच्छा** नहीं हुआ कि जब यह अपेक्षा की जा रही थी कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप आने ही वाला है तब यह सूचना मिली कि इस प्रारूप को तैयार करने वाली कस्तूरीरंगन समिति का कार्यकाल एक बार और बढ़ा दिया गया। इस समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है। उम्मीद की जाती है कि अब इस समिति का कार्यकाल और अधिक बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी नई शिक्षा नीति को सामने लाने के काम में पहले ही बहुत अधिक देरी हो चुकी है। यह देरी इसलिए अस्वीकार्य है, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह स्पष्ट ही है कि इस कार्यकाल में नई शिक्षा नीति के प्रारूप को अमल में लाना मुश्किल ही होगा। अभी तो यह प्रारूप आया ही नहीं है। जब प्रारूप आएगा तब उस पर चर्चा के लिए समय चाहिए होगा। इस चर्चा के बाद सरकार के पास शायद ही इतना समय बचे कि वह उसे क्रियान्वित करने के आवश्यक कदम उठा सके। यह आश्चर्यजनक है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात भाजपा के घोषणापत्र में होने के बावजूद उसे समय पर तैयार नहीं किया जा सका। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वयं के अलावा अन्य किसी को दोष नही दे सकता। यह एक प्राथमिकता वाला कार्य था और उसे तत्परता के साथ किया जाना चाहिए था। कोई नहीं जानता कि कस्तूरीरंगन समिति के पहले सुब्रमण्यम समिति की ओर से तैयार नई शिक्षा नीति के मसौदे को क्यों अस्वीकार कर दिया गया। कम से कम तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नई शिक्षा नीति का जो मसौदा सामने आए वह सरकार की अपेक्षाओं और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि नई शिक्षा नीति के मसौदे में क्या खास बातें होंगी, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। हर स्तर पर शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं। वर्तमान में जो शिक्षा नीति अमल में लाई जा रही है वह 1986 में तैयार की गई थी। हालांकि 1992 में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन तब भी वह वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। इस पर आश्चर्य नहीं कि नई शिक्षा नीति को तैयार करने में हो रही देरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नाखुशी प्रकट की है। उसके नाखुश होने के पर्याप्त कारण हैं। नई शिक्षा नीति को तैयार करने में जो अनावश्यक देरी हुई उसके कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब तक जो कुछ किया है वह अपर्याप्त साबित हो रहा है। यह सही है कि प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के अभाव में वे तमाम कार्य नहीं हो सके जो अब तक हो जाने चाहिए थे। बेहतर यह होगा कि नई शिक्षा नीति को तैयार कर रही समिति को यह संदेश दिया जाए कि वह देर आए दुरुस्त आए उक्ति को चरितार्थ करने का काम करे। ऐसा होने पर ही देरी के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा।

# एक और लापरवाही

**अधिकांश सरकारी** अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश सरकार के मंसूबे को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी लापरवाही और उदासीनता के चलते अति महत्वपूर्ण कार्य भी अधूरे पाए जा रहे हैं। सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। संविदा व सेवाप्रदाता के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड करने और इन रिक्तियों को पोर्टल के माध्यम से ही भरने का आदेश है, बावजूद इसके विभाग इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली और प्रमुखताओं के अभ्यस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। सरकार द्वारा 21 जून, 2017 को शासनादेश जारी करने के बावजूद सिर्फ पांच विभागों ने ही रिक्तियों की सूचना सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड की है। अब एक बार फिर से प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन ने निर्देश जारी किया है। प्रमुख सचिव ने समस्त विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं।

**आखिर एक साल पहले जारी किए गए शासनादेश के अनुपालन की खोज-खबर किसी ने क्यों नहीं ली**

यह पहला मौका नहीं जब किसी मामले में विभागों की लापरवाही उजागर हुई हो। सवाल उठता है कि आखिर एक साल पहले जारी शासनादेश के अनुपालन की खोज-खबर किसी ने क्यों नहीं ली। यह लापरवाही किसके खाते में जाएगी। साफ बात है कि भले ही सरकार कोई आदेश-निर्देश या शासनादेश जारी करती हो, पर लंबे समय तक उसकी कोई सुध ही नहीं लेता है। नतीजतन अधिकारी और कर्मचारी भी ढीला-ढाला रवैया अपनाते हैं या उसमें भ्रष्टाचार का घुन लग जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जब भी ऐसा कोई आदेश-निर्देश या शासनादेश जारी हो, उसके अनुपालन की स्पष्ट जिम्मेदारी भी तय कर दी जाए, ताकि बाद में चेतावनी की बजाय सीधे कार्रवाई अमल में लाई जाए।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी




## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उपराज्यपाल के साथ दिल्ली सरकार का गतिरोध अड़ियल रवैये का ही परिणाम है?**




### आज का सवाल

क्या डोप टेस्ट से पंजाब में ड्रग समस्या का समाधान होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
**Y** –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# समर्थन मूल्य से आगे की चुनौती



**केसी त्यागी**

**कृषि व कृषक सुरक्षा की ओर एक कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार के समक्ष चुनौती होगी कि कृषि उत्पादों की खरीदारी नए एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए**

देर से ही सही, लेकिन खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लागत का डेढ़ गुना किया जाना खेती-किसानी के संकट निवारण की दिशा में बड़ी पहल है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी में उत्साहवर्धक बढ़ोतरी से न सिर्फ कृषि जगत को राहत मिली, बल्कि पिछले कई वर्षों से फसलों के गिरते दाम व एमएसपी न मिलने से हताश किसानों को उम्मीद की एक किरण नजर आई है। खरीफ वर्ष 2018-19 के लिए साधारण धान के एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल के इजाफे के साथ इसकी कीमत 1750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है जो कि घोषित 1166 रुपये के लागत मूल्य से 50.09 फीसदी अधिक है। पिछले वर्ष धान का एमएसपी 1550 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले कई वर्षों से इसके एमएसपी में सांकेतिक बढ़ोतरी की तुलना में इस बार धान उत्पादकों को प्रति क्विंटल 200 रुपये की भारी बढ़ोतरी मिलेगी। इससे पूर्व राजग शासन के दौरान इसमें महज 50 से 80 रुपये प्रति क्विंटल की ही बढ़ोतरी की गई थी। वर्ष 2012-13 के संप्रग शासन के दौरान धान के एमएसपी में सर्वाधिक 170 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी जिसके बाद से किसान एमएसपी के अच्छे दिनों की बाट जोह रहे थे।

सच है कि नए एमएसपी में सभी फसलों की लागत पर 50 फीसदी का लाभकारी मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि इन फसलों की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है जो अन्य वर्षों की तुलना में अधिक है। वहीं इनके एमएसपी में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान है। लागत पर 50 फीसदी का मूल्य देने के अंकगणित में यह भी अनुमानित है कि इससे राजकोष पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इस बीच महंगाई दर में वृद्धि से आशंकित अर्थशास्त्री समेत चंद अर्थजीवियों की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली रही। अफसोसजनक है कि जब कभी ऋण माफी, खाद्य सब्सिडी, एमएसपी या अन्य किसानी सहयोग की पहल होती है तो वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्साहवर्धक सराहना नहीं की जाती। हजारों करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी तथा लाखों करोड़ रुपये का एनपीए उन्हें नहीं खटकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से राजकोष पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ आया था। लगभग एक करोड़ कर्मचारियों के उत्थान की दिशा में 60 करोड़ कृषक परिवार बाधक नहीं बनते, लेकिन किसान हितैषी नीतियों पर संस्थागत हायतौबा किसान विरोधी मंशा को ही दर्शाती है।

इस फैसले से वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा फसलों की कीमत डेढ़ गुना करने का बजटीय आश्वासन तो जरूर पूरा हुआ है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी व प्रधानमंत्री द्वारा स्वामीनाथन फॉर्मूले को हूबहू लागू कर एमएसपी के अतिरिक्त 50 फीसदी का लाभकारी मूल्य दिए जाने का वादा अधूरा प्रतीत होता है। नई घोषणा में लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर किसान व उनके संगठनों की मांग पूरी नहीं हुई है जिस कारण तमाम किसान संगठनों ने अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दर्ज कराई है।




अवधेश राजपूत

यह सच है कि कृषि उत्पादों के दाम तय करने वाले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा लागत मूल्य तय करने वाली प्रक्रिया लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। मौजूदा लागत मूल्य निर्धारण में भी ए-2, एफ-एल को आधार बनाकर फसलों की लागत मूल्य के अनुपातिक एमएसपी बढ़ाया गया है जबकि किसान संगठनों द्वारा सी-2 प्रणाली को आधार मानकर लागत के अतिरिक्त 50 फीसदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग रही है। संगठनों का आरोप है कि उन्हें सी-2 व्यवस्था के तहत 50 फीसदी का लाभकारी मूल्य दिए जाने का वादा किया गया था। इन आरोप-प्रत्यारोप के बीच तथ्यों की स्पष्टता हेतु ए 2-एफ-एल की तकनीकी को समझना आवश्यक है। सीएसीपी द्वारा तीन चरणों में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है। प्रक्रिया ए-2 के तहत किसानों द्वारा खेती में उपयुक्त सभी सामग्री जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी तथा मशीनों का किराया शामिल होता है। चूंकि कृषक परिवार भी खेती में शामिल होते हैं तो उनका पारिवारिक श्रम यानी एफ-एल को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा जाता है जो ए-2 और एफएल का योग होता है। इन दोनों से इतर 'व्यापक लागत' यानी सी-2 व्यवस्था के तहत अन्य लागतों के साथ अपनी भूमि व पूंजी का किराया भी शामिल होता है जो ए2-एफएल से अधिक व्यापक होता है यही किसानों की मांग रही है। सी-2 प्रणाली के तहत धान के नए एमएसपी में महज 15 फीसदी का इजाफा हुआ है जबकि ए 2-एफएल के तहत बढ़ोतरी का आंकड़ा 50 फीसदी तक पहुंच रहा है।

राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने भी एमएसपी निर्धारण की इसी प्रक्रिया की सिफारिश की है। उनके द्वारा यह विचार भी रखा जा चुका है कि किसानों की कर्ज माफी के बजाय सरकार द्वारा सी-2 व्यवस्था से एमएसपी प्रदान करने की पहल ज्यादा कल्याणकारी होगी। हालांकि बजट में उत्पादों की डेढ़ गुना कीमत देने के वादे के बीच कृषि भूमि के किराये को लागत मूल्य से वंचित रखने की सिफारिश किसान संगठनों को पहले ही निराश कर चुकी है। एमएसपी में अनुशंसित स्तर से कम हुई बढ़ोतरी के असंतोष के बावजूद किसानी संकट को काबू करने की दिशा में यह निश्चित ही सराहनीय प्रयास है।

कृषि व कृषक सुरक्षा की ओर एक कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार के समक्ष चुनौती होगी कि प्रत्येक फसल उत्पाद की खरीदारी नए एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए। हाल के महीनों में कई राज्यों से मूंगफली, कपास, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, ज्वार, अरहर, मक्का और उड़द के मंडी भाव और एमएसपी में बड़ा भारी अंतर देखा गया है। कहीं धान में नमी की मात्रा बताकर किसानों को एमएसपी से दूर रखा जाता है तो कभी उत्पादन में बहुतायत या अन्य विवशताओं के कारण औने-पौने दाम पर उन्हें अनाज बेचने को मजबूर होना पड़ता है। संसद में भी यह बात स्वीकारी जा चुकी है कि किसानों को निर्धारित एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना की पहल सराहनीय रही, लेकिन इससे एमएसपी प्रणाली की विफलता भी सार्वजनिक हुई है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को वचनबद्ध सरकार को न सिर्फ 23 फसलों के एमएसपी अदायगी पर सख्त नजर रखनी होगी, बल्कि आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मौसमी फल, सब्जियों तथा दूध के लाभकारी मूल्य की भी कड़ी निगरानी रखनी होगी।

चुनावी आचार संहिता के कारण आगामी बजट में किसानों के लिए विशेष घोषणा की गुंजाइश नहीं दिखती। ऐसे में निर्धारित एमएसपी के भुगतान में कड़ी निगरानी किसानों के लिए तात्कालिक राहत एवं अन्य आयोगों की तर्ज पर किसान आयोग का गठन कर उनके अनुकूल नीति-निर्माण व समस्याओं का त्वरित निपटारा मौजूदा सरकार की बड़ी सफलता होगी।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)
**response@jagran.com**

# साझे की नौका के अकेले यात्री



**आशुतोष झा**

**भाजपा के लिए आगामी आम चुनाव की लड़ाई उतनी आसान नहीं लगती जितनी दो साल पहले दिख रही थी**



बीते कुछ महीनों में राजनीति बहुत तेजी से बदलती दिख रही है। बड़ी संख्या में विपक्षी दल और नेता अपने सिद्धांत और छवि के विपरीत भी चलने की तैयारी का संकल्प जता रहे हैं। बयानों में तो एक कदम और आगे बढ़कर इतना बड़ा दिल दिखाया जा रहा है जैसे उन्हें व्यक्तिगत से ज्यादा इसकी चिंता है कि वह केंद्र की राजग सरकार के खिलाफ सामूहिक अभियान में शामिल दिखें। यह बड़ी घटना है जिसके कारण इसकी संभावना भी बढ़ गई है कि इस बार शायद विपक्षी एकजुटता दिखे जो जाहिर तौर पर राजग के लिए बड़ी चुनौती होगी। खासतौर पर तब जबकि उसके अपने कुनबे में ही बिखराव की आग सुलग रही हो। खैर, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस एकजुटता का उद्देश्य भी एक है? क्या ऐसे सभी दलों और नेताओं का दिल सचमुच बड़ा हो गया है? या इस कोशिश में जुटा हर दल एक दूसरे का कंधा ढूंढ रहा है, निजी लाभ की गुंजाइश तलाश रहा है? ऊपर से शांत और भीतर से उफान लिए यह संघर्ष दोनों गठबंधनों के वर्तमान व भावी दलों के बीच भी दिख रहा है और दलों के नेताओं के बीच भी। लड़ाई का मैदान भले ही राष्ट्रीय है, लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धा भी हैं जो क्षेत्रीय और व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठ पाने में असमर्थ हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में विपक्षी महागठबंधन को लेकर कुछ तंज कसे। जाहिर तौर पर कुछ चीजें बहुत साफ-साफ दिख रही हैं। मसलन विपक्ष में इसकी होड़ है कि सबसे ज्यादा एंटी मोदी कौन दिखता है? दरअसल यह सीधे तौर पर उक्त नेता को मोदी के सामने तो खड़ा करता ही है, जनता के उस वर्ग में भी लोकप्रिय बनाता है जो भाजपा या राजग के खिलाफ है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह हमलावर दिख रहे हैं, उसके पीछे शायद यही आकलन हो। ध्यान रहे कि महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर बार-बार सवाल पूछे जाते हैं जिसका अब तक कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यह सार्वजनिक है कि महागठबंधन में जिन दलों को गिना जा रहा है उसमें कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अनुभव और उम्र के लिहाज से राहुल सबसे युवा हैं। इसका अहसास भी संभावित दोस्तों की ओर से कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौड़ में ही नहीं है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की चुप्पी का क्या...।

उन्होंने तो उस बयान के बाद भी कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें अखिलेश ने मायावती को नेता मानने और ज्यादा सीटें देने तक का खुला संदेश दे दिया था। देखा तो यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में भी मायावती का जिक्र बड़े अदब के साथ किया जाता है, लेकिन बसपा की ओर से कोई खुला रिस्पांस नहीं दिख रहा है। क्यों? ममता बनर्जी महागठबंधन की हिमायती हैं, लेकिन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का खेमा बनाकर और परोक्ष रूप से उसका नेतृत्व लेकर यह जताने में कोई गुरेज नहीं करती हैं कि उनकी स्वीकार्यता बड़ी है। दिल्ली आने पर भी उनकी कोशिश यह होती है कि कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता उनके पास आएं। हालांकि उन्हें जानने वाले मानते हैं कि उनकी दिलचस्पी फिलहाल पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि वह महागठबंधन की शर्त खुद तय करना चाहती हैं।

चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वह जानते हैं कि उनकी हद आंध्र प्रदेश है। तब क्या यह नहीं मानना चाहिए कि क्षत्रपों की दिल्ली में हो रही गतिविधि दरअसल राज्यों में खुद को ताकतवर दिखाने के लिए हो रही है। एक तरीके से उप-राष्ट्रवाद को उभारा जा रहा है। खुद को संबंधित राज्यों में सबसे बड़ा और प्रभावी नेता स्थापित करने की कोशिश हो रही है। यह किसी से नहीं छिपा है कि चंद्रबाबू को अपने विरोधी दल वाइएसआर कांग्रेस के दबाव में राजग से बाहर जाना पड़ा था। राज्य में उन्हें हर कदम पर जवाब देना पड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में पहचान कम से कम नेतृत्व और चेहरे के आधार पर तो उन्हें वाइएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी से थोड़ा आगे खड़ा कर ही सकती है। मजे की बात यह है कि अपना कद बढ़ाने की कवायद न सिर्फ गठबंधन के अंदर, बल्कि दलों के अंदर भी चल रही है। वामदल महागठबंधन में बहुत अहमियत नहीं रखते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी ताकत नहीं बची और केरल में वह कांग्रेस का साथ नहीं दे सकता। दिल्ली में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो उनके विरोधी धड़े के बड़े नेता व केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ममता और अन्य दो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ खेमा बनाते दिखे। वह तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भी गए। हाल में जब देश के कई मुख्यमंत्री योग दिवस का बहिष्कार कर रहे थे तो पिनरई योग की प्रशंसा में खुल कर बोले। कड़वी सच्चाई यह है कि कर्नाटक के दक्षिण में न तो कांग्रेस के पास ताकत है और न ही भाजपा के पास। यहां क्षेत्रीय दलों में जिस तरह की खींचतान है उसमें गठबंधन तो संभव है, लेकिन महागठबंधन नहीं। जिस तरह आपसी खींचतान चल रही है उसमें असरदार बनने के लिए कई गुत्थियां सुलझाई जानी बाकी हैं, लेकिन यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जितना शोर हो रहा है उसका सत्तर फीसद भी जमीन पर उतरा तो भाजपा और राजग की राह बहुत कठिन होगी।

लेकिन प्रधानमंत्री के बयान का दूसरा अकथित पहलू यह भी है कि भाजपा के लिए यह लड़ाई उतनी आसान नहीं जितनी दो साल पहले दिख रही थी। इसमें शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने प्रशासन में कुशलता दिखाई और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन को आसमान पर पहुंचाने की सोच और दक्षता को साबित किया। पर यह वक्त है गठबंधन बनाने, संवारने और संभालने का। पूर्वोत्तर में जरूर कुछ दल राजग का हिस्सा बने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना समेत दूसरे छोटे दल नाराज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सरकार में रहते हुए भी आए दिन बगावती सुर में बोलती है। बिहार में जदयू के छोटे नेताओं के बयान विपक्षी दलों को खुश होने का मौका देते हैं और बड़े नेता चुप रहकर इसे तूल। पिछली लोक सभा में सौ फीसद सीट भाजपा को देने वाले राजस्थान में अंदरूनी घमासान है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में चार-पांच महीने लग गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लाख कोशिशों के बावजूद पंद्रह साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं बच सकते हैं। जब विपक्षी खेमा उत्साह से लबरेज हो तो इसे सामान्य मानना महंगा पड़ सकता है। अमित शाह को दिखाना होगा कि वह कुशल संगठनकर्ता ही नहीं गठबंधन के माहिर शिल्पकार भी हैं।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)
**response@jagran.com**

## ऊर्जा

### अगला अवसर

'नो' अंग्रेजी का शब्द जन-जन में लोकप्रिय है। यह एक बहुत साधारण सा शब्द है जिसका प्रयोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति दिन में किसी न किसी कारण से अवश्य करता है। यह शब्द एवं कार्य की संरचना पर निर्भर करता है कि 'नो' शब्द को किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। 'नो' शब्द कई बार व्यक्ति को बहुत परेशान करता है तो कभी 'एन ओ' नो का अर्थ 'नेक्स्ट अपॉरच्युनिटी' यानी अगला अवसर बन जाता है। सैम्युअल स्माइल्स भी कहते हैं कि 'जो लोग खुद के लिए कोई अवसर खोजने के लिए संकल्पवान हैं, उन्हें हमेशा पर्याप्त अवसर मिलेंगे और अगर उन्हें नहीं मिलते हैं तो वे अवसर बना लेंगे।'

जो व्यक्ति अवसरों को बनाना जानते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना जानते हैं, कुशल रणनीति से चलना जानते हैं उनके लिए 'नो' कभी भी 'नहीं' बनकर नहीं आता। उनके लिए वह हमेशा अगला अवसर लेकर ही आता है। 'अगला अवसर' उनका जीवन बदल देता है और उन्हें शिखर पर पहुंचा देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अवसर उनके पास भाग्य से आते हैं, जबकि यह मात्र उनका भ्रम होता है। जो लोग बुलंद हौसले वाले होते हैं वे कभी भी हार नहीं मानते। यदि उन्हें जीवन में अनेक बार 'नो' सुनने को मिलता है तो वे इसका अर्थ 'नहीं' न लेकर अगला अवसर लेते हैं और अपनी मेहनत से खुद अपने लिए अवसर बना लेते हैं। मेहनती लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे बार-बार 'नो' सुनकर अगला अवसर संघर्ष करते हुए स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं।

जीवन हमें सिर्फ एक बार मिलता है। इसमें मिलने वाले 'नो' को हम 'नहीं' समझकर चुप बैठ जाते हैं या 'अगला अवसर' समझकर आगे बढ़ते रहते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। जीतते वहीं हैं जो 'नो' में छिपे अगले अवसर को पहचान लेते हैं और उस अगले अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को बदलकर रख देते हैं। यह याद रखिएगा कि आपको जितनी बार 'नो' सुनने को मिलता है, आप उतनी ही बार अगले अवसर की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो कार्य करते हैं, उन्हें 'नो' सुनने को मिलता ही है। आप भी 'नो' सुनकर रुके नहीं बढ़ते रहें, बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आएंगे और आपकी एक नई पहचान बनाएंगे।

रेनू सैनी

## पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

### आय के स्रोत बढ़ाने की जरूरत

कर्ज माफी का महंगा सौदा शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने किसानों की कर्ज माफी के बदले इनके लिए ऐसी नीतियां बनाने की राय दी है जिससे उन्हें कर्ज के बोझ तले दबने की नौबत न आए। मेरा मानना है कि हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि किसानों के लिए कर्ज माफी डूबते को तिनके का सहारा बन सकता है। प्रकृति के कहर के कारण अगर किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसको उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए और अगली फसल के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती है तो वह भी आसानी से मिलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ किसान कृषि के नाम पर लिए कर्ज को दूसरे कामों के लिए प्रयोग करते हैं तो इसमें गलती सरकारों की ही है। आखिर वे क्यों नहीं किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की जांच करवाती हैं? अक्सर देखा गया है कि मौसम की बेरुखी कारण किसानों की फसल तबाह हो जाती है। इस कारण किसानों को अगली फसल की पैदावार के लिए और अपने खर्चे चलाने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है, क्योंकि किसानों की आय के दूसरे कोई साधन नहीं होते हैं। किसानों को फसलों, फलों और सब्जियों के उचित दाम भी नहीं मिलते हैं। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को घरेलू उद्योगों से जोड़े ताकि उनकी आय के स्रोत बढ़ें।

raju09023693142@yahoo.com

### कर्नाटक में कर्जमाफी

कर्नाटक सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के अपने वादे को पूरा किया, लेकिन सरकार ने इससे हुए नुकसान की भरपाई पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी से करने का फैसला लिया है, जिसकी मार आम आदमी पर पड़ेगी। इसके साथ ही किसानों पर भी इसकी दोहरी मार पड़ेगी। जहां एक तरफ फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने-आने में परिवहन का खर्च बढ़ेगा वहीं खेत में पानी के लिए उन्हें अधिक पैसे चुकाने होंगे। जिससे निश्चित तौर पर खेती की लागत बढ़ेगी और किसान कर्ज से जुड़ेंगे। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि क्या सरकार किसानों की कर्जमाफी को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा तक ही सीमित रखना चाहती है? सरकार को किसानों के फसल के पर्याप्त मूल्य की व्यवस्था करने की जरूरत है।

नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

### जिम्मेदार कौन?

स्कूलों में दिए जा रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता पर अगर नजर डाली जाए तो तकरीबन सभी राज्यों में इसके हालात एक जैसे ही हैं। यह गुणवत्ताविहीन भोजन खाकर कितने बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो कई बच्चे मौत की नींद सो जाते हैं। इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुलती। इससे प्रशासन की सक्रियता का पता चलता है। इस मिड-डे मील के खाने से अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं होती? इसमें गलती किसकी है? इसकी भी जांच अवश्य होनी चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, आइसीएआइ, नोएडा

### अफवाह से बचें युवा

हमारी संस्कृति महान संत - महात्माओं के आदर्शों की बुनियाद पर खड़ी है। इनकी अमरवाणियों ने हमारी आस्था को बल दिया है। फिर हमारी आस्था इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि हम किसी की जान ले लें? अहिंसक देश में यह हिंसक भीड़ कहां से आई? मॉब लिंचिंग का जहर कौन फैला रहा है? हमें सवालों के जवाब ढूढ़ने होंगे, वरना अहिंसा परमो धर्मः की अवधारणा इस भीड़तंत्र के सामने घुटने टेक देगी। सच तो यह है कि इस देश के स्वार्थी राजनेताओं ने विकास के रास्तों में जाति और धर्म की बारूदी सुरंगे बिछा रखी हैं। अफवाहों से बचने की आवश्यकता है, वरना विकसित सूचना तंत्र से नई पीढ़ी को दी जाने वाली हिंसक खुराकें आने वाले दिनों को ज्यादा डरावना बना देंगी।

mkmishralz@yahoo.in

### प्लास्टिक बना बड़ा दुश्मन

बीते कुछ वर्षों में गायों की बीमारियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि आगरा की गऊशाला की रिपोर्ट के अनुसार हर साल सैकड़ों की संख्या में गायों की मौत हो रही है। इनकी मृत्यु की बढ़ती संख्या के कारण का पता लगाने के लिए सड़क पर मरी हुई 25 गायों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पाया गया कि उनके पेट से पॉलीथिन, बोतल के ढक्कन, लोहे की कीले, सिक्के, ब्लेड, सेफ्टी पिन, पत्थर इत्यादि जैसी चीजें निकली। एक गाय के पेट से तो 70 किलों प्लास्टिक की पॉलीथिन निकली।

विगत कुछ वर्षों में दुनिया में प्लास्टिक का उपयोग बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, जिसका कारण है इसके उत्पादन में वृद्धि और बढ़ती मांग। एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष 30 से 40 लाख टन प्लाष्टिक का देश में उत्पादन किया जाता है और लगभग 15 लाख टन कचरा प्लास्टिक रूप में होता है। प्लास्टिक ना केवल जानवरों के लिए अपितु मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। साइंटिफिक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि गाय और भैंस के दूध, गोबर और मूत्र में प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में लगभग 300 से 400 साल लगते हैं और इतने लम्बे समय में बढ़ता उत्पादन और खपत आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व में फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है, जिसने प्लास्टिक की सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा 2020 तक वह प्लास्टिक मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश होगा। यह विषय एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का विषय बन चुका है, क्योंकि इस बार पर्यावरण दिवस बीट द पॉलीथिन के साथ मनाया गया। भारत सरकार को भी इसको रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।

अखिल सिंघल, दिल्ली विश्वविद्यालय

## ट्वीट-ट्वीट

नफरत फैलाने वाला और आतंक का हिमायती जाकिर नाइक आज मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। एक दिन पहले ही मलेशिया ने साफ किया कि वह उसे भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेगा। यह भारत के दिशाहीन कूटनीतिक प्रयासों और नाइक की पैठ और प्रभाव को बखूबी बयां करता है।

आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

जयंत सिन्हा का बचाव करके भाजपा प्रवक्ता उनका भला नहीं, बल्कि और बुरा ही कर रहे हैं। भारत सरकार के किसी भी मंत्री को हिंसक भीड़ का हिस्सा बने लोगों के साथ जश्न नहीं मनाना चाहिए। चूंकि पीड़ित एक 'अपराधी' था तो इस आधार पर भी उनका बचाव समझ से परे है।

तवलीन सिंह@tavleen_singh



अपने प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध करते हुए दीपा कर्माकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तुर्की में आयोजित अंतराराष्ट्रीय स्पर्धा के वॉल्ट मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई।

विजय कुमार सिंह@Gen_VKSingh

थाईलैंड की गुफा में फंसे हुए बच्चों के बचाव अभियान पर मुझे लगता है कि कोई बेस्टसेलर किताब आएगी या बड़े स्तर पर फिल्म बनाई जाएगी। इस अभियान में शामिल प्रत्येक शख्स की कोशिशों को नमन।

ऋचा सिंह@richa_singh

## जनपथ

बरसे पानी तो कहीं कहीं बरसती आग,
कुदरत से सब पा रहे अपना-अपना भाग।
अपना-अपना भाग न पर्यावरण बचाया,
तो कुदरत का कोप समझ लो सिर पर आया।
अब ना वह दिन दूर बूंद को मानुष तरसे,
या बदरा घनघोर प्रलय की बारिश बरसे।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 355